MR. CHAIRMAN: I am equally concerned. This question belongs to the North-East Which is a neglected area.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not disputing that.

MR. CHAIRMAN: So, I want to give time to all the Members belonging to the North-East.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not disputing that. ...*(interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I understand my duty. Shri Parag Chaliha.

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, first of all, I thank you for taking that much interest in the proverbilly neglected North-East. As is known to the hon. Minister, who happens to be very well known to me, and also to others there, assurances were earlier given on several requests made from our side regarding the extension of timings. The number of trips by the Rajdhani Express to and from North-East should be increased to, at least, five a week. It has running, for the last few months, three times a week, both up and down. I request the hon. Minister to kindly see to it that the trips are increased at least from three to five a week because of the onrush of passengers to and from Nagaland in the North-East. We have been making this particular demand, for the last two or three years, from the North-East side.

श्री नीतीश कुमार: एम०पी०ज० की मीटिंग में हम इन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर सकेंगे।

Property owned by Indian Women

*449. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether a study published in the Sunday Times, dated June 14, 1998, has revealed that women own only one hundredth part of World's property;

(b) if so, what part of property in India is owned by the Indian women population, as per the said study and as per Government's independent assessment; and

(c) whether there is any policy and action plan to give the women their due part in property in India; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The International Labour Organisation (ILO), in its issue"World of Work" of March, 1997 has quoted the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) to the effect that women earn only 10 percent of the world's income and own less than 10 percent of the world's income and own less than 10 percent of the world's property which has been referred to in Sunday Times. However, the publication has not indicated the part of the property in India owned by Indian Women. The ILO's report however, does not refer to any study on the basis of which this statement is made. Government has not made any independent assessment in this regard.

(c) Government is committed to the economic empowerment of women by ensuring that women get greater access to property rights including land rights. As per the recommendations of the National Perspective Plan (1988-2000); State Governments have been advised to give joint title to husband and wife in all developmental activities involving transfer of assets like pattas for ceiling land, government and village common land, house sites, houses, tree pattas and beneficiary oriented economic units. State Governments have also been advised to amend Section 6 of Hindu Succession Act, 1956 to provide coparcenary rights in coparcenary property to daughters of a deceased coparcenary in a Joint Hindu

Family. Under Schemes for providing income generating assets like IRDP, there is earmarking of 40% of benefits for women. Allotment of houses under Indira Awas Yojana is made in the name of the female member or in the joint name of husband and wife.

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने कहा है कि महिलाओं को सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में विश्व भर में जो अधिकार है। उसमें 10 प्रतिशत से भी कम उनके स्वामित्व में है और आय अर्जित करने वालों में भी 10 प्रतिशत है। लेकिन भारतीय महिलाओं की स्थिति यह है कि पहले तो वह बेटी है, फिर पत्नी, अगर वह विधवा है तो उसको इसका अधिकार है। लेकिन अधिकतर भारतीय औरतें अपने को अधिक सौभाग्यवती समझती हैं अगर वह पति के घर में सदा सुहागिन रहे। उसको बेटी के रूप में संपत्ति में अधिकार हैं लेकिन पत्नी के रूप में पति की सम्पत्ति का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसका पति जीवित है। विधवा को पति की सम्पत्ति पाने का अधिकार है। महिलाओं को खेती में अधिकार नहीं है, एनसेस्ट्रल प्रापर्टी में अधिकार नहीं है। पत्नी को यह अधिकार नहीं है, बेटी को बेटी के रूप में संपत्ति पाने का अधिकार है। तो क्या औरतें अपनी सारी जिंदगी बेटी बने रहने की सोचें या फिर जो उसके सारे जीवन की साधना कि वह सौभाग्यवती रहना चाहती है, इक्वल पार्टनर कहलाती है, अर्धांगिनी है तो क्या पति की सपंत्ति में, शादी एक कानूनी प्रक्रिया भी है और यह पवित्र होने के अलावा..

श्री सभापति: आपका सवाल हो गया।

श्रीमती वीणा वर्मा: तो क्या महिलाओं को पति की चल-अचल सम्पत्ति में शादी के दिन से बराबर का स्वामित्व देने के बारे में विचार करें और संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव लायेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: संविधान के अनुसार तो हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार कई प्रकार से है। संविधान के अनुसार किसी भी तरह से जेंडर का डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी इसमें व्यवस्था है। लेकिन जो सम्पत्ति के उत्तराधिकार का कानून है उसमें संशोधन की हमने बार-बार राज्य सरकारों को हिदायतें दी है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन भी किया है, संशोधन भी किया है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, हम इन तमाम प्रश्नों और इन तमाम समस्याओं के बारे में एक सुविचारित राय जानने के लिए उसको कहते रहते है। हमारा मंत्रालय प्रस्तावों को विभिन्न मंत्रालयों तक भेजता है। लेकिन ...**(व्यवधान)**... मेरी पूरी बात सुनिए आप इतनी जल्दी में क्यों हैं?

हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को बार-बार यह लिखा है, अन्य मंत्रालयों को कहते रहते हैं। हमारा मंत्रालय इस काम को अंजाम देने वाला मंत्रालय नहीं है। यह इन तमाम समस्याओं को एकत्रित करके विभिन्न मंत्रालयों को पहुंचाने वाला है। हमारी सिफारिश इस मामले में यह रही है कि उत्तराधिकार कानून में संशोधन किए जाएं और महिलाओं को सम्पत्ति के मामले में अधिकार दिए जाएं जो मंशा संविधान की उनको देने की है। लेकिन इस कानून को लाने की व्यवस्था तभी होगी जब कि इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें और बाकी सिफारिशें हमारे पास आ जाएं।

The question was actually asked on the of the House by Shrimati Veena Verma.

उन पर सुविचारित अपना मन्तव्य हम प्रकट करेंगे। मंत्रालय की दृष्टि से महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना उचित है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

MISS MABEL REBELLO: Sir this is an important question. We want a Half-an-hour Discussion on it.

MR. CHAIRMAN: You please give notice. We will have a Half-an-hour Discussion.

श्रीमती कमला सिन्हा: सर, इस पर एक बहस हो जानी चाहिए।

श्री सभापति: हां, मैंने कहा है कि आप एक हाफ एन आवर का नोटिस दीजिए।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Increase in HIV afflicted Persons in the Country

*441. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a sharp increase in HIV-AIDS case all over the country;